



# एग्री आर्टिकल्स

(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)

वर्ष: 03, अंक: 02 (मार्च-अप्रैल, 2023)

[www.agriarticles.com](http://www.agriarticles.com) पर ऑनलाइन उपलब्ध

© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

## प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): कौशल विकास, सुगठित विकास

(शिखा भुकल, ईला रानी एवं दीक्षा रानी)

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

संवादी लेखक का ईमेल पता: [shikhab2011995@gmail.com](mailto:shikhab2011995@gmail.com)

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। 21 राज्यों ने खरीफ 2016 में योजना लागू की जबकि 23 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने रबी 2016-17 में योजना लागू की। खरीफ 2016 के अनुसार 31.03.2017 को आंकड़ों के अनुसार लगभग 3.7 करोड़ किसानों को 128568.94 करोड़ रुपये की बीमा राशि के लिए 16212 करोड़ रुपये के प्रीमियम पर 3.7 करोड़ करोड़ रुपये भूमि का बीमा किया गया है।

यह योजना फसल की विफलता के खिलाफ एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है। इस योजना में सभी खाद्य और तिलहन फसलें और वार्षिक / वाणिज्यिक बागवानी फसलें शामिल हैं, जिनके लिए पिछली उपज के आंकड़े उपलब्ध हैं और जिनके लिए सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के तहत अपेक्षित संख्या में फसल कटाई प्रयोग किए जा रहे हैं। यह योजना सूचीबद्ध सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। कार्यान्वयन एजेंसी का चयन संबंधित राज्य सरकार द्वारा बोली के माध्यम से किया जाता है। यह योजना अधिसूचित फसलों के लिए फसली ऋणधकेसीसी खाता लेने वाले कर्जदार किसानों के लिए अनिवार्य है और अन्य के लिए स्वैच्छिक है। यह योजना कृषि मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जा रही है।

PMKVY ने कई सुधार किए हैं अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। PMKVY के मुख्य आकर्षण में से एक है सरकार पर किसी ऊपरी सीमा का अभाव प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMKVY): एक सिंहावलोकन सब्सिडी, भले ही शेष प्रीमियम 90 हो प्रतिशत। योजना में लागू की गई थी फरवरी 2016 और एक प्रारंभिक आवंटित किया गया था 5,500 करोड़ रुपये का केंद्र सरकार का बजट 2016-17 के लिए 18। इसमें 154 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। योजना से पता चलता है कि यह के लिए महत्वपूर्ण है सरकार सभी किसानों का बीमा करेगी वित्तीय सहायता और ऋण के प्रवाह की गारंटी फसल-उपज नुकसान की स्थिति में उन्हें।

### कैसे कराएं बीमा?

पीएम किसान फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा कराना काफी आसान है। जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड बना रखा है या कोई अन्य कृषि ऋण ले रखा है तो वे उसी बैंक से अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ ज्यादा नहीं करना होगा। बस बैंक में एक फॉर्म भरना होगा। बैंक के पास किसान की जमीन और अन्य कागजात होते हैं, इसलिए आसानी से बीमा हो जाता है।

जिन किसानों ने लोन नहीं ले रखा है, वे भी किसी भी बैंक से यह बीमा करा सकते हैं। हर जिले में सरकार ने फसल बीमा करने के लिए एक या एक से अधिक बीमा कंपनियों को अधिकृत कर रखा है। बैंक इनके संपर्क में रहते हैं। किसान बैंक में आधार कार्ड, जमीन से संबंधित कागजात, पटवारी से लिया गया खेत में बोई गई फसल का विवरण और वोटर कार्ड जैसी आईडी ले जाकर फसल बीमा करवा सकता है।

**कितना मिलता है क्लेम?**

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अलग-अलग फसलों के लिए बीमा राशि अलग-अलग है। कपास की फसल के लिए अधिकतम 36,282 रुपये, धान के लिए फसल के लिए 37,484 रुपये, बाजरा की फसल के लिए 17,639 रुपये, मक्का की फसल के लिए 18,742 रुपये और मूंग की फसल के लिए 16,497 रुपये प्रति एकड़ राशि मिल सकती है।

**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फायदे**

- सभी फसलों पर लागू।
- प्रीमियम में किसान का हिस्सा- वन सीजन वन रेट।
- प्रीमियम पर कैपिंग हटाने के कारण बीमित राशि में कोई कमी नहीं।
- किसानों के हिस्से से अधिक का प्रीमियम सरकार द्वारा पूरी तरह से वहन किया जाता है।
- अधिसूचित फसलोंक्षेत्र के लिए सभी ऋणी किसानों का नामांकन।
- बैंकों के माध्यम से अऋणी किसानों को प्राथमिकता।
- दावों की गणना और भुगतान की समय-सीमा में काफी कमी आई है।
- बुआई से पहले से लेकर कटाई के बाद के नुकसान तक व्यापक जोखिम कवरेज।
- रोगी गई बुवाई रू बीमित राशि के 25% तक के दावे।
- मध्य-मौसम प्रतिकूलताओं के कारण खाते में भुगतान।
- ओलावृष्टि, भूस्खलन और बाढ़ जैसे स्थानीय जोखिमों को कवर किया गया।
- कटाई के 2 सप्ताह बाद तक खेत में कटाई के बाद का नुकसान।

**PMKVY की विशेषताएं:**

1. किसानों का कवरेज इस योजना में शामिल हैं कर्जदार किसान (जिन्होंने ए ऋण), गैर-कर्जदार किसान (स्वैच्छिक पर आधार), किरायेदार किसान और बटाईदार।
2. फसलों का कवरेज हर राज्य ने अधिसूचित किया है रबी के लिए फसलें (प्रमुख फसलें) और खरीफ ऋतु। प्रीमियम की दरें अलग-अलग होती हैं सभी मौसमों में।
3. प्रीमियम दरें: PMKVY तय करती है दो प्रतिशत का एकसमान प्रीमियम बीमा राशि, सभी के लिए किसानों द्वारा भुगतान किया जाना है खरीफ फसल, राशि का 1.5 प्रतिशत सभी रबी फसलों के लिए बीमा, और पांच प्रतिशत वार्षिक वाणिज्यिक और के लिए बीमा राशि की बागवानी फसलों या बीमांकिक दर, जो भी कम हो, जिसकी सरकारी प्रीमियम सब्सिडी कोई सीमा नहीं है।
4. क्षेत्र आधारित बीमा इकाईरू PMKVY एक क्षेत्र दृष्टिकोण पर काम करता है। इस प्रकार, सभी एक विशेष क्षेत्र में किसानों को भुगतान करना होगा समान प्रीमियम और समान दावा है भुगतान। क्षेत्र दृष्टिकोण कम कर देता है नैतिक खतरे और प्रतिकूल का जोखिम चयन।
5. जोखिमों का कवरेज इसका उद्देश्य रोकथाम करना है बुवाई/रोपाई जोखिम, खड़े होने का नुकसान फसल, कटाई के बाद के नुकसान और स्थानीयकृत आपदाओं। बीमा राशि के बराबर है प्रति हेक्टेयर खेती की लागत गुणा अधिसूचित फसल के प्रस्तावित क्षेत्र द्वारा किसान द्वारा बीमा के लिए
6. नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोगरू यह अनुशंसा करता है कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग। के लिये उदाहरण के लिए ड्रोन का उपयोग कम करने के लिए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट ( CCE ) परंपरागत रूप से फसल नुकसान का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है और देरी को कम करने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करना ऐप ऑनलाइन पर क्रॉप कटिंग डेटा अपलोड करके दावा निपटान में।
7. बीमा कंपनियों के लिए क्लस्टर दृष्टिकोणरू यह बीमा के बीच ₹1 बिलियन को प्रोत्साहित करता है कंपनियों को आवंटित किए जाने से पहले जिला निष्पक्ष प्रतियोगिता सुनिश्चित करें। कार्यात्मक बीमा कार्यालय होगा शिकायत के लिए स्थानीय स्तर पर गठित निवारण, एक फसल बीमा के अलावा सभी ऑनलाइन प्रशासन के लिए पोर्टल प्रक्रियाओं।

चुनौतियां

- अन्नकृषी किसानों का कवरेज बढ़ाने पर ध्यान ।
- प्रीमियम सब्सिडी के संवितरण में विलंब ।
- CCE के संचालन में रिसाव ।
- उपज डेटा प्रस्तुत करने में विलंब ।
- उपज डेटा में विवाद ।
- बैंकों से सूचना का वास्तविक समय प्रवाह ।
- स्मार्टफोन/ CCE कृषि ऐप का उपयोग ।